# King George's Medical University

**Uttar Pradesh, Lucknow - 226003, India**

This is certified that the Government Orders regarding the reservation policy issued by Uttar Pradesh Government have been incorporated in the University reservation policy.

16/6/25

**(Prof. Sandeep Bhattacharya)**
Deputy Registrar
K.G. Medical University U.P.
Lucknow

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस0डब्ल्यू0/एस0पी0 587
लाइसेन्स नं0 एस0 पी0 44
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशलन रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

**उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित**

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट

**भाग-3 खण्ड (क)**
**(उत्तर प्रदेश विधन मण्डल के विधेयक)**
**लखनऊ, बुधवार, 23 मार्च, 1994**
चैत्र 2, 1916 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश सरकार**

# विधायी अनुभाग-1

**संख्या - 488/सत्रह-वि-1-1 (क) - 6-1994**
**लखनऊ, 23 मार्च 1994**
**अधिसूचना**

# विविध

---

"भारत का संविधान" अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)

अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, ओर उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

Registrar
King George Medical University
Lucknow

# अधिनियम

---

**भारत गणराज्य के पैतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-**

---

**परिभाषाएं**

1- (1) **यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित संक्षिप्त नाम जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और प्रारम्भ आरक्षण) अधिनियम**, 1994 **कहा जाएगा।**

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2- इस अधिनियम में -

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है :

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है:

(ग) "लोक सेवाआं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं :-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी :-

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) के यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत के कम न हो :

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई नियम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हों या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वृत्त समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो :-

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है :-

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है।

(घ) किसी रिक्त के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

| | |
|---|---|
| **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण** | 3-(1) **लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (**5**) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :-**<br>(क) अनुसूचित जातियों के मामले में इक्कीस प्रतिशत<br>(ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में दो प्रतिशत<br>(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में सत्ताइस प्रतिशत<br>परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।<br>(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों मे से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनाधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय।<br>(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी, भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी।<br>(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों को अनुपलब्धता के कारण उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुछ आरक्षण उस वर्ष में कुछ रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।<br>(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचना ओदश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक यह समाप्त न हो जाय।<br>(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता मे सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है। तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।<br>(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये। |
| **अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति** | 4- (1) **राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा उत्तरदायित्व सौंप सकती है।** |

Archana
Registrar
King George's Medical University
Lucknow

| | |
|---|---|
| | (2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो। |
| **शास्ति** | 5-(1) **कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो यह, दोष सिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।**<br>(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।<br>(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे। |
| **अभिलेख मांगने की शक्ति** | 6- **यदि राजय सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्ही भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।** |
| **चयन समिति में प्रतिनिधित्व** | 7- **राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसे रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारिकों के नाम - निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।** |
| **छूट और शिथिलीकरण** | 8-(1) **राज्य सरकार, धारा 3 के उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।**<br>(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा, या साक्षात्कार के लिए फीस छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, लागू रहेंगे जब तक उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय। |

Registrar
King George Medical University
Lucknow

| | |
|---|---|
| जाति प्रमाण-पत्र | 9- इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा। |
| कठिनाईयों को दूर करना | 10- यदि इस अधिनियम के उपबन्धों की कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। |
| सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण | 11- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी। |
| नियम बनाने की शक्ति | 12- राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है। |
| अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति | 13- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित समझा जायेगा। |
| आदेशों इत्यादि का रखा जाना | 14- धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं। |
| अपवाद | 15-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नही होंगे जिनमे चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।<br>स्पष्टीकरण :- जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार -<br>(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर, या<br>(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,<br>इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।<br>(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकार सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।<br>Registrar<br>King George Medical University<br>Lucknow |

| | | |
|---|---|---|
| निरसन और अपवाद | 16-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश आरक्षण) अभिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।<br>(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवत्त थे। | उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1993 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1994 |

## अनुसूची-एक

(देखिए धारा 2 (ख)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अहीर | 29. | नायक |
| 2. | अरख | 30. | फकीर |
| 3. | काछी | 31. | बंजारा |
| 4. | कहार | 32. | बढ़ई |
| 5. | केवट या मल्लाह | 33. | बारी |
| 6. | किसान | 34. | बैरागी |
| 7. | कोइरी | 35. | बिन्द |
| 8. | कुम्हार | 36. | बियार |

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | कुर्मी | 37. | भर |
| 10. | कम्बोज | 38. | भुर्जी या भड़भूजा |
| 11. | कसगर | 39. | भठियारा |
| 12. | कुंजड़ा या राईन | 40. | माली, सैनी |
| 13. | गोसाई | 41. | मनिहार |
| 14. | गूजर | 42. | मुराव या मुराई |
| 15. | गड़ेरिया | 43. | मोमिन (अंसार) |
| 16. | गद्दी | 44. | मिरासी |
| 17. | गिरि | 45. | मुस्लिम कायस्थ |
| 18. | चिकवा (कस्साव) | 46. | नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी |
| 19. | छीपी | 47. | मारछा |
| 20. | जोगी | 48. | रंगरेज |
| 21. | झोजा | 49. | लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत |
| 22. | डफाली | 50. | लोहार |
| 23. | तमोली | 51. | लोनिया |
| 24. | तेली | 52. | सोनार |

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | **दर्जी** | 53. | **स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)** |
| 26. | **धीवर** | 54. | **हलवाई** |
| 27. | **नक्काल** | 55. | **हज्जाम (नाई)** |
| 28. | **नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)** | | |

# अनुसूची - दो

(**देखिये धारा** 3 (1)

1- निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री :-

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य : या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो : या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक, शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है : या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क' / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारिक जो उपश्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है : या

(ड) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का काई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रूपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2- चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय मे लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वितीय वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

3- किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4- किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाईयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रूपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन मे कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5- किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियम सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़ कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रूपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

6- किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम दस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

रजि. नं. एल. डब्लू./एन०. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जनवरी, 1996

पौष 15, 1917 शक सम्वत्

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG—1

No. 34/XVII-V-1-1 (KA) 44-1996

*Dated Lucknow, January 5, 1996*

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

THE following President's Act enacted on January 5, 1996 is published for general information:—

## THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1996

(PRESIDENT'S ACT NO. 1 OF 1996)

*[Enacted by the President in the F[illegible] the Republic of India]*

AN

A[illegible]

*to constitute a Commission for the S[illegible] Pradesh for Backward Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to provide for matters Connected therewith or incidental*

Registrar
King George Medical University
Lucknow

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995, the President is pleased to enact as follows :—

## CHAPTER-I

### *Preliminary*

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 17, 1994.

Definitions

2. In this Act—

(*a*) "backward Classes" means such classes of citizens as are defined in clause (*b*) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time ;

(*b*) "Commission" means the State Commission for Backward Classes constituted under section 3 ;

(*c*) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman ;

(*d*) "Schedule" means Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

## CHAPTER—II

### *The State Commission for Backward Classes*

Constitution of the State Commission for Backward Classes

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the State Commission for Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The headquarters of the Commission shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.

(3) The Commission shall consist of a Chairman and four other Members nominated by the State Government from amongst persons of eminence, ability and integrity :

Provided that four members including the Chairman shall be from the backward classes.

Term of office and conditions of service

4. (1) The Chairman and every other member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.

(2) A Member may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from the office of Chairman or as the case may be, of Member but shall continue to hold office until his resignation is accepted.

(3) The State Government shall remove a person from the office of Member if that person —

(*a*) becomes an undischarged insolvent ;

(*b*) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude ;

Registrar
King George's Medical University
Lucknow

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court ;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting ;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission ; or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of backward classes or the public interest :

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(5) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

*Officers and other employees of the Commission*

5. (1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Secretary and other officers and employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

*Salaries and allowances to be paid out of grants*

6. The salaries and allowances payable to the Chairman and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

*Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission*

7. No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

*Procedure to be regulated by the Commission*

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

Registrar
King George Medical University
Lucknow

CHAPTER—[illegible]

*Functions and powers of the Commission*

*Functions of the Commission*

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely :—

(a) the Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in the Schedule and hear complaints of wrong inclusion or non-inclusion of any backward class in the Schedule and tender such advice to the State Government as it deems appropriate ;

(b) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the backward classes under any law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards;

(c) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of right and safeguards of the backward classes;

(d) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the backward classes and to evaluate the progress of their development;

(e) to present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(f) to make in such reports recommendations, as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the backward classes; and

(g) to discharge such other function in relation to the protection, welfare, development and advancement of the backward classes as may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before each House of the State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

Powers of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document; 45 of

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Periodic revision of the Schedule by the State Government

11. (1) The State Government may at any time, and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of the Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the Schedule with a view to excluding from the Schedule those classes who have ceased to be backward classes or for including in the Schedule new backward classes.

(2) The State Government shall while undertaking any revision referred to in sub-section (1) consult the Commission.

CHAPTER IV

*Finance, accounts and audit*

Grants by the State Government

12. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being untilised for the purposes of this Act. 45 of

Registrar
King George Medical University
Lucknow

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

13. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed, Accounts and audit

(2) The accounts of the Commission shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) The auditor shall have such powers of requiring the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and for inspecting any of the offices of the Commission as may be prescribed.

14. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government. Annual Report

15. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before both the Houses of the State Legislature. Annual report and audit report to be laid before the state legislature

CHAPTER—V

*Miscellaneous*

16. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. Chairman, Members and employees of the Commission to be public servants

45 of 1860

17. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of, the Chairman and Members under sub-section (8) of section 4 and of officers and other employees under sub-section (2) of section 5 ;

(b) the form in which the annual statements of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 13 ;

(c) the form in, and the time at which the annual report shall be prepared under section [illegible] ;

(d) any other matter which is required to be or may be prescribed.

18. Whoever, being [illegible] obey any order or direction of the Commission under section 10, disobeys such order of direction shall be punishable under sections 174, 175, [illegible] or 180 of the Indian Penal Code, as the case may be. Penalty

45 of 1860

19. No court shall take cognizance of any of the offences specified in section 18 except on the complaints in writing of the Chairman or a Member or of an officer of the Commission authorised in this behalf by the Commission. Cognizance of offences

Registrar
King George Medical University
Lucknow

Protection of action taken in good faith

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to remove difficulties

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act. U. P. Act no. 1 of 1904

Saving

22. Notwithstanding anything in this Act the Commission constituted by the Uttar Pradesh Government Order No. 22/16/92-Ka-2-93, dated March 9, 1993, shall be deemed to have been duly constituted under the provision of this Act and the term of three years of the Chairman and other Members of the said Commission shall be computed from the date on which they had assumed charge of their respective offices.

Repeal and Savings

23. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Second) Ordinance, 1995 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 34 of 1995

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have done or taken under this Act.

SHANKER DAYAL SHARMA,
*President.*

---

K. L. MOHANPURIA,
*Secretary to the Government of India.*

Reasons for the enactment

In pursuance of the Judgement of the Hon'ble Supreme Court in the Mandal Commission Case (Indira Sahani *Vs.* Union of India), the State Government constituted a commission for Backward Classes by notification dated 9th March, 1993. It was desired to regulate the constitution of the said Commission by an enactment. It was further decided that besides examining the request for inclusion of any class of citizens as backward class and complaints of wrong inclusion or non-exclusion in the list of Backward Classes, the Commission may also perform other spec[illegible] view to safeguard of the interest and welfare of the Backward Classes.

2. Since the State Legislature was not in session [illegible] action in the matter was necessary, the U[illegible] for Backward Classes Ordinance, 1994 (U. P. Ordinance No. 26 of 1994) was promulgated by the Governor on the 17th November, 1994. To replace the provisions of [illegible] Ordinance the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Bill, 1995 was introduced in the Uttar Pradesh Legislative Council on the 6th February, 1995 but since the said Bill could not be passed by the Uttar Pradesh Legislative Council, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Ordinance, 1995 (U.P. Ordinance No. 12 of 1995) was promulgated by the Governor on the 30th March, 1995 to keep the provisions of the aforesaid Ordinance in force.

Registrar
King George Medical University
Lucknow

3. Since the aforesaid Bill could not be passed in the session of the State Legislature, commencing from the 14th July, 1995, and remained pending with the Legislative Assembly, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Second) Ordinance, 1995 (U. P. Ordinance No. 34 of 1995) was promulgated by the Governor on the 25th August, 1995 to replace the provisions of the aforesaid U. P. Ordinance No. 12 of 1995.

4. The President issued a proclamation on the 18th October, 1995 under Article 356 of the Constitution, in relation to the State of Uttar Pradesh, declaring, *inter alia*, that the powers of Legislature of the State shall be exercised by or under the authority of Parliament. Parliament has, under Article 357 (1) (*a*) of the Constitution, now conferred on the President, the powers of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws *vide* the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996).

U. P. Act no. 1 of 1994

5. The said Ordinance could not be replaced by an Act and the Ordinance is expiring on the 7th January, 1996. It is, therefore, decided that the said Ordinance shall be replaced by a President's Act.

6. Under the proviso to sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996) the President shall, before enacting any President's Act, consult a Committee constituted for the purpose consisting of the members of both the Houses of Parliament. As the said committee has yet not been constituted and the matter is very urgent, it is proposed to enact the measure without reference to the said Committee.

U. P. Ordinance no. 34 of 1995

K. B. SAXENA,
*Secretary to the Government of India.*

By order,
R. D. MATHUR,
*Pramukh Sachiv.*

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 276 सा० विधायी—(4542)-1996-850 (मैक०)।

क्रम संख्या–242

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस डब्लू/एन.पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू पी० – 41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग 1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 31 अगस्त, 2002
भाद्रपद 09, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या 1576/सत्रह–वि–1–1(क)–11–2002
लखनऊ, 31 अगस्त, 2002

### अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 29 अगस्त, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

Registrar
King George Medical University
Lucknow

### उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

# अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन )अधिनियम, 2002 कहा जायेगा

(2) धारा 2, धारा 3, के खण्ड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वितीय परन्तुक को छोड़कर धारा 3 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) धारा 4, धारा 5 और धारा 6, 15 सितम्बर 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जायेगें धारा 3 के खण्ड (क) के शेष उपबन्ध, खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग) 25 जून 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है।

(क) धारा–2 में खण्ड (ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:–

"(ख) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है",

(ख) खण्ड (ख–1), (ख–2), (ख–3) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1), (2), (3), के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात:–

"(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में — इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में — दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के मामले में — सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन [illegible] अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो [illegible] लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि [illegible] रिक्तियों का आरक्षण [illegible], उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पाचस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और [illegible] सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नही होगा:

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध के उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे

Registrar
King George Medical University
Lucknow

रह जाए तो ऐसी रिक्ति को अग्रनीत किया जायेगा और उसे उसी वर्ष में या पश्चात्वर्ती वर्ष मे या भर्ती के वर्षो में पृथक वर्ग की रिक्त के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायगा और उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्त की गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

(3) जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई रिक्त उपधारा (2) के अधीन तीन विशेष भर्ती करने के पश्चात् भी बिना भरी रह जाय तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती है।'',

(ख) (एक) उपधारा (3–क),(–3ख) निकाल दी जायगी,

(दो) उपधारा (4) निकाल दी जायगी;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात:–

''(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमे आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायेगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायगा जब तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायगा और तत्पश्चात् जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।''

अनुसूची–एक का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाएगी, अर्थात्–'

## ''अनुसूची–एक''

**[धारा 2 (ख) देखिये]**

Registrar
King George Medical University
Lucknow

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
2. सोनार, सुनार, स्वर्ण[illegible]
3. जाट
4. कुर्मी [illegible] कुर्मी–मल्ल,कुर्मी–सैंथवार
5. गिरी
6. गूजर
7. गोसाई
8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी,
9. कम्बोज
10. अरख, अर्कवंशीय
11. काछी, काछी–कुशवाहा, शाक्य
12. कहार, कश्यप
13. केवट, मल्लाह,निषाद

14. किसान
15. कोइरी
16. कुम्हार, प्रजापति
17. कसगर
18. कुजड़ा या राईन
19. गडेरिया, पाल, बघेल
20. गद्दी, घोसी
21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
22. छीपी, छीपा
23. जोगी
24. झोजा
25. डफाली
26. तमोली, बरई, चौरसिया
27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक
28. दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ
29. धीवर
30. नक्काल
31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
32. नायक
33. फकीर
34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
35. बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान
36. बारी
37. बैरागी
38. बिन्द
39. बियार
40. भर, राजभर
41. भुर्जी, भड़भुजा, भूँज, कांदू, कसोंधन
42. भठियारा
43. माली, सैनी
44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर
45. लोहार, लोहार–सैफी
46. लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया चौहान
47. रंगरेज, रंगवा
48. मारछा
49. हलवाई, मोदनवाल
50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51. राय सिक्ख
52. सक्का–भिश्ती, भिश्ती–अब्बासी
53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54. कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
55. नानबाई
56. मीरशिकार
57. शेख सरवरी (पिराई) पीराही
58. मेव, मेवाती
59. कोष्टा / कोष्टी
60. रोड़
61. खुमरा, संगतराश, हंसीरी
62. मोची
63. खागी
64. तंवर सिंघाड़िया
65. कतुआ
66. माहीगीर
67. दांगी
68. धाकड़
69. गाड़ा
70. तंतवा
71. जोरिया
72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
73. कलाल, कलवार, कलार
74. मनिहार, कचेर, लखेरा
75. मुराव, मुराई, मौर्य
76. मोमिन [illegible]
77. मुस्लिम कायस्थ
78. [illegible]
79. नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)"

Registrar
King George Medical University
Lucknow

**अनुसूची–दो का संशोधन**

5–मूल अधिनियम की अनुसूची–दो, में–

(क) अनुच्छेद एक में शब्द "या रहा हो" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के उपखण्ड (ड.) में हिन्दी पाठ में आये हुए शब्द "अस्थाई" के स्थान पर शब्द "स्थाई" रख दिया जायगा;

**अनुसूची–तीन का संशोधन**

6– मूल अधिनियम की अनुसूची–तीन निकाल दी जायेगी।

**निरसन और अपवाद**

7– (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश,2002 एतद्द्वारा निरसित किए जाते है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2002 तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीनकृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

**ए0 बी0 शुक्ला,**

प्रमुख सचिव।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

## उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया है। लोक सेवाओं और पदों में जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को दो श्रेणियों में और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में अग्रतर वर्गीकृत करने, और उन्हें लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने और निम्नलिखित की भी व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2001) द्वारा उक्त अधिनियम को संशोधित किया गया था–

(क) किसी भर्ती के वर्ष में उस वर्ष की रिक्तियों या संवर्ग के पचास प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान करना;

(ख) किसी आरक्षित श्रेणी की बिना भरी हुई रिक्तयों को भरने के लिए अधिकतम तीन विशेष भर्ती के प्रतिबन्ध को समाप्त करना;

(ग) किसी आरक्षित वर्ग की बिना भरी रिक्तयां को पृथक वर्ग की रिक्त के रूप में तब तक अग्रनीत करना जब तक वे भर न जाय;

(घ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से संबंधित बिन्दुओं को इंगित करते हुए संवर्ग की सदस्य–संख्या पर रोस्टर जारी करना।

2–सन् 2001 के उपर्युक्त अधिनियम को अखिल भारतवर्ष छात्र युवा बेरोजगार फ्रन्ट द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गयी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21 जनवरी, 2002 के अपने अंतरिम आदेश [illegible] रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान सन् 2011 के उपर्युक्त अधिनियम के अनुसरण में कोई कार्यकारी आदेश पारित नही किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश को देखते हुए लोक सेवाओं और पदों में

Registrar
King George Medical University
Lucknow

रिक्तयों को भरने के लिए भर्तियाँ नही की जा सकी और विभिन्न विभागों में भारी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए थे। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि सन् 1994 के उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को, जैसा वे उक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2002 द्वारा संशोधन के पूर्व विद्यमान थे, पुनःस्थापित किया जाय।

3— चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 जून 2002 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 2 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

4— चूंकि ऊपर प्रथम पैरा में निर्दिष्ट (क) से (घ) के उपबंधो को आर0 के0 सब्बरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को सम्मिलित करने के लिए और संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा अन्तःस्थापित संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4—ख) के उपबन्धों के प्रकाश में बनाया गया था, जिन्हें उपर्युक्त उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2000 द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया था, अतएव यह विनिश्चय किया गया था कि 1994 के उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जाय।

5— चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और ऊपर पैरा 4 में निर्दिष्ट विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 जून 2002 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2002 प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

No. 982(V)-V-1-1(Ka) 22/2000

Lucknow : Dated August 05, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pichhda Varg Rajya Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 4, 2001.

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2001

[U.P. Act no. 18 of 2001]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.

Short title — 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2001.

Amendment of section 4 of President's Act no. 1 of 1996 — 2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 1996,—

(a) in sub-section (1) the first proviso shall be omitted and in the second proviso for the words "Provided further that" the words "Provided that" shall be substituted;

(b) sub-sections (1-A) and (1-B) shall be omitted.



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

[illegible] the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996 provides for the Constitution of the Commission and for [illegible] of the Chairman and the members thereof. [illegible] the Chairman or every member shall hold [illegible] or till the attaining the age of sixty-five [illegible] take advantage of persons of social background having long experience it has been decided to amend the said Act to omit the provisions relating to age limit for holding office of the Chairman or the member.

[illegible] Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

By order,
D.V. SHARMA,
*Pramukh Sachiv.*

[illegible]
[illegible]

No. 1183(2)/V-1-07-1(ka)29/2007
Dated Lucknow, July 9, 2007

NOTIFICATION

**Miscellaneous**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pichhda Varg Rajya Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 7, 2007.

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. Act No. 19 of 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Commission for Backward Classes Act, 1996.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2007. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

2. In section [illegible] Pradesh State Commission for Backward Classes Act [illegible] referred to as the principal Act, for sub-section (1) the following [illegible] shall be substituted, namely :- Amendment of section 3 of U.P. Act no. 1 1996

"(1) The Commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and [illegible] other Members to be nominated by the State Government from amongst persons of [illegible] and integrity".

3. In section 4 of the Principal Act,- Amendment of section 4

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely :-

[illegible] of every other member shall [illegible] year from the date he assumes office :

Provided that the Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such during the pleasure of the State Government.

(b) sub-section (2) shall be omitted.

(c) after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely :-

"(4) (a) The Chairman shall be having the status of a Minister of the State.

(b) The Vice-Chairman shall be having the status of the Deputy-Minister of the State".

U.P. Ordinance no. 11 of 2007 4. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Registrar
[illegible] Medical University
Lucknow

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996 (Uttar Pradesh Act no. 1 of 1996) has been enacted to constitute a Commission for Backward Classes. With a view to making the working of the Commission more dynamic it was decided to amend the said Act to provide that the said Commission shall be constituted with a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen members of which fifteen members (including the Chairman) shall be from amongst Backward Classes, the Chairman, the Vice-Chairman or every member shall hold office for a term of one year from the date he assumes office or during the pleasure of the State Government and the Chairman and the Vice-Chairman shall be having the status of the Minister of State and the Deputy Minister respectively.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 13 of 2007) was promulgated by the Governor on June 13, 2007.

Thereafter it has been decided to omit the restriction of caste with respect to the nomination of persons for the offices of the Chairman, Vice-Chairman and members of the Commission.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with the modification as aforesaid.

By order,
VIRENDRA SINGH,
*Pramukh Sachiv.*

Registrar
Medical University
Lucknow

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 237 राजपत्र (हि०)—2007—(868)—599 प्रतियाँ—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 88 सा० विधायी—(72)—2007—850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।

क्रम-संख्या–68

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 मार्च, 2014

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 323 / 79-वि-1–14-1(क)7-2014

लखनऊ, 4 मार्च, 2014

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 4 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 17 फरवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (3) में,--

(क) शब्द "सत्रह अन्य सदस्य" के स्थान पर शब्द "पच्चीस अन्य सदस्य" रख दिये जायेंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:--

"परन्तु यह कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** :-- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द 'अल्पसंख्यक' का अर्थ वही होगा जैसा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) में परिभाषित है।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) का अधिनियमन राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में यह प्रावधान किया गया था कि आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे। चूँकि अन्य सदस्यों की उक्त संख्या अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं थी और उक्त आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई सदस्य उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं था, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त उपधारा को संशोधित करके अन्य सदस्यों की संख्या को सत्रह से बढ़ाकर पच्चीस करके यह व्यवस्था की जाय कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि उक्त आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग संशोधन अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

---

No. 323(2)/LXXIX-V-1-14-1(Ka)7-2014

*Dated Lucknow, March 4, 2014*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pichhada Varg Rajya Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 04, 2014.

Registrar
King George Medical University
Lucknow

E UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(AMENDMENT) ACT, 2014
(U.P. ACT NO. 4 OF 2014)
*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2014. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on February 17, 2014.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3),– Amendment of section 3 of President's Act no. 1 of 1996

(a) *for* the words "seventeen other members" the words "twenty-five other members" shall be *substituted*;

(b) the following proviso and Explanation shall be *inserted*, in the end, namely:–

"Provided that at least one representative from minority community shall be nominated as member in the Commission.

*Explanation:*–For the purposes of this Act the word 'minority' shall have the same meaning as defined in the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 (U.P. Act no. 22 of 1994)."

Repeal and saving 3. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2014

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action is taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996 (President's Act no. 1 of 96) has been enacted to constitute a Commission for Backward Classes other than the Scheduled Castes Scheduled Tribes in the State. Sub-section (3) of section 3 of the said Act provided that the nmission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen other members nominated by State Government from amongst persons of eminence, ability and integrity. Since the said number of er members was not sufficient to solve the problems of Other Backward Classes and there was no nber of the Other Backward Classes of minority community in the said Commission to represent them. as decided to amend the said sub-section to increase the number of other members from seventeen to ity-five and to provide that at least one representative from minority community shall be nominated as iber in the said Commission.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to ement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes endment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 2 of 2014) was promulgated by the Governor on iary 17, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.B. SINGH,
*Pramukh Sachiv.*

यू०पी०–ए०पी० 814 राजपत्र(हि०)–2014–(1832)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
यू०पी०–ए०पी० 142 सा० विधायी–2014–(1833)–500 प्रतिया (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

# उत्तर प्रदेश सरकार

**विधायी अनुभाग-1**

संख्या 535 / सत्रह-वि-1-2(क) 7-1995

लखनऊ,13 मार्च,1995

## अधिसूचना

## विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1)द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1995 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1995) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लियें राज्य आयोग अध्यादेश, 1995**

**(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 1995)**

(भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियो से भिन्न पिछड़े वर्गो के लिए आयोग के गठन और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## अध्यादेश

चूंकि, उपर्युक्त विषयों की व्यवस्था करने लिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 1994 को उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1994, प्रख्यापित किया गया था।

और, चूंकि उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग विधेयक 1995 दिनांक 6 फरवरी, 1995 को उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् में पुनः स्थापित किया गया था और वह उक्त सदन में लम्बित है।

और, चूकि राज्य विधान मंडल सत्र में नही है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

## अध्याय एक
## प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, अध्यादेश, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 17 नवम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2- इस अध्यादेश में-

(क) ''पिछड़े वर्गो'' का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गो से है जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है:

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा3 के अधीन गठित पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग से है :

(ग) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है :

(घ) ''अनुसूची'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक से है।

## अध्याय दो
## पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन

3- (1) राज्य सरकार इस अध्यादेश के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग कहा जायेगा।

Registrar
King George's Medical University
Lucknow

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें

(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों

|  |  |  |
|---|---|---|
| | | में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे। परन्तु चार सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, पिछड़े वर्गों से होगे। |
| पदावधि और शर्तें | 4- | (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पदधारण करेगा। |

(2) कोई सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष के या सदस्य के पद से किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है किन्तु जब तक उसका त्याग-पत्र स्वीकृत नहीं कर लिया जाता वह अपने पद पर बना रहेगा।

(3) राज्य सरकार किसी 'व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-

(क) अननुमोचित दिवालिया हो जाय

(ख) किसी अपराध के लिये जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो सिद्ध दोष और कारावास से दण्डित किया जाय :

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी समक्ष न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय।

(घ) कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने अयोग्य हो जाय

(ड़) आयोग से अनुपस्थिति रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थिति रहे।

या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना पिछड़े वर्गों के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन, हटाया नही जायेगा। जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया

Registrar
King George's Medical University
Lucknow

हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय-वेतन और भत्ते उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

| | | |
|---|---|---|
| आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी | 5- | (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो।<br>(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाय। |
| वेतन और भत्ते का भुगतान अनुदान से किया जाना। | 6- | अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियो को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित है, का भुगतान धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा। |
| रिक्तियां इत्यादि से आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी। | 7- | आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी। |
| आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना | 8- | (1) आयोग जब आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।<br>(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।<br>(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगें। |

Registrar
King George Medical University
Lucknow

## अध्याय तीन
## आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कृत्य

9- (1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात-

(क) अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे:

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।

(ग) पिछड़े वर्गो के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।

(घ) पिछड़े वर्गो के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेगा और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्याकंन करेगा।

**राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;**

(च) पिछड़े वर्गो के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों की, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करेगा।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

(छ) पिछड़े वर्गो के संरक्षण, कल्याण, विकास और

अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायं निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष/आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही और एकसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

**आयोग की शक्ति**

10- आयोग को धारा, 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषतः न्मिनलिखित बातों के संबंध में शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात-

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना, करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(च) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाय।

**राज्य सरकार द्वारा अनुसूची का नियतकालिक पुनरीक्षण**

11- (1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची से उन वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, निकालने की दृष्टि से [illegible] को सम्मिलित करने के लिए अनुसूची का [illegible] कर सकती है और इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर

Registrar
King George's Medical University
Lucknow

और उसके प्रश्चात् प्रत्येक दस वर्ष की उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर ऐसा पुनरीक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेंगी।

## अध्याय चार
## वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षण

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

12- (1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये उपभोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि, जैसा राज्य सरकार उचित समझे आयोग को भुगतान करेंगी।

(2) आयोग इस अध्यादेश के अधीन कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशि जैसी वह उचित समझे खर्च कर सकता है, और ऐसी राशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझी जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

13- (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, की जायेगी।

(3) लेखा परीक्षक को बहियों,लेखों, संबंधित बाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा कर[illegible] किसी कार्यालय का निरीक्षण करने के [illegible], जैसी विहित की जाय।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

वार्षिक रिपोर्ट

14- आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधानमण्डल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना

15- राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की कार्यवाही और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार करने, यदि कोई हों, के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उसको प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगी।

## अध्याय पांच
## विविध

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

16- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगें।

नियम बनाने की शक्ति

17- (1) राज्य सरकार,अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है अर्थात्-

(क) धारा-4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा-5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और [illegible] सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें।

(ख) प्रपत्र, जिसमें धारा-13 की उपधारा(1) के अधीन वार्षिक लेखा का विवरण रखा जायेगा।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

(ग) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

**शक्ति**

18- जो कोई, धारा 10 के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आवद्ध होते हुए, इस आदेश या निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करें वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174,175,176,178,179 या 180 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो दण्डनीय होगा।

**अपराध का संज्ञान**

19- कोई न्यायालय धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नही।

**सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण**

20- किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अध्यादेश तदन्तर्गत बनाए गये नियमों के उपबंधो के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हों या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जाएगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगीं।

**कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

21- (1) इस अध्यादेश के उपबंधो को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अध्यादेश के उपबंधो से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की सम[illegible] उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नही दिया जायेगा।

[illegible] प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 [illegible]धारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) की अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश पर उसी प्रकार

Registrar
King George Medical University
Lucknow

लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

अपवाद

22- इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए, भी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 22/16/92-का-2-93, दिनांक 9 मार्च 1993 द्वारा गठित आयोग इस अध्यादेश के उपबंधो के अधीन गठित आयोग समझा जायेगा और उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के तीन वर्ष के कार्यकाल की संगणना उनके द्वारा अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी।

निरसन और अपवाद

23- (1) उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1994 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

**मोती लाल वोरा**
राज्यपाल उत्तर प्रदेश

आज्ञा से
**नरेन्द्र कुमार नारंग**
प्रमुख सचिव

Archana

Registrar
King George Medical University
Lucknow

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्याः- 22/16/92-का-2/1995

लखनऊः दिनांक 8 दिसम्बर, 1995

**अधिसूचना**

प्रकीर्ण

रिठ याचिका सं0 631/94 अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य में दिनांक 4-9-1995 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उ0प्र0 लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 उ0प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-2 को निरस्त कर दिया है और यह निर्देश दिए हैं कि उ0प्र0 राज्य में 1995-86 के शैक्षणिक सत्र मे केन्द्र सरकार के मेमोरेन्डम दिनांक 8-9-1993 मे निर्धारित क्रीमिलेयर का अनुसरण किया जायेगा।

अतएव उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 उ0प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की धारा-13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची दो को निम्नवत् संशोधित करते हैं और यह भी निर्देश देते हैं कि अनुसूची जो केन्द्र सरकार के मेमोरेन्डम दिनांक 8-9-1993 जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति मे लागू हो सके, शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक सत्र 1995-96 के प्रवेश मे भी लागू समझी जायेगी।

**संशोधन**

**उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची दो रख दी जाएगी, अर्थात:-**

**अनुसूची-दो**

**(धारा 3(1) देखिए)**

<u>एक संवैधानिक पद</u>

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री.....

(क) भारत के राष्ट्रपति

(ख) भारत के उप राष्ट्रपति

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,

(घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और

Registrar
King George Medical University
Lucknow

सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक,
(ड.) इसी प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति।

दो-सेवा श्रेणी:-

<u>(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क/श्रेणी एक अधिकारी:-</u>

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री:-

(क) जिनके मात पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/ श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता दोनो समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हो किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय,

(घ) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थाई अक्षमता सेग्रसित हो जाय और ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उनमे किसी अन्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधिं के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ड.) जिनके माता पिता दोनो समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हो और ऐसे माता पिता दोनों की मृत्यृ हो जाये या वे स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाएं और दोनों की ऐसी मृत्यु का अक्षमता के पूर्व उसे किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

<u>(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी</u>

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री

(क) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से केवल पिता समूह ख/श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क/श्रेणी एक में आ जायें।

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यृ हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय और उसमें से किसी एक को ऐसी मृत्यृ या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त

Registrar
King George Medical University
Lucknow

राष्ट्र-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ है।

(घ) जिनके माता पिता में से पिता समूह क/श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख/श्रेणी दो की अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय।

स्पष्टीकरण- इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद ''स्थायी अक्षमता का'' तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा के बाहर हो जाय।

**(ग) <u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी:-</u>**

ऊपर उपश्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैको,बीमा,संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों। इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा।

**<u>तीन- अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों की धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नही है।)</u>**

ऐसे माता पिता, जिनमें से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौ सेना, वायु सेना और अर्द्ध सैनिक बलों या उसके समकक्ष पदों पर हों के पुत्र या पुत्री,

स्पष्टीकरण:- इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ जोड़ा नहीं जाएगा।

**<u>चार----व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी छः में विनिर्निष्ट मानदण्ड निम्न लिखित पर लागू होंगे</u>**

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर, परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता वास्तुविद,फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकूद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और।

(ख) धन्धे व्यापार और उद्यो[illegible]

Registrar
King George Medical University
Lucknow

**<u>स्पष्टीकरण:-</u>** (एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो [illegible] ख/श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो [illegible] विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इस[illegible] जोड़ी जाएगी।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख/श्रेणी दो या निम्न

श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

पांच-सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि जोत

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं उसकी पत्नी/पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित है, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो, के पुत्र या पुत्री--

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानून अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत बराबर या उससे अधिक हो, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हों) सिंचित भूमि की साविधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो।

**स्पष्टीकरण--** पद "कानूनी अधिकतम जोत सीमा" और "परिर्वतन फार्मूला" का अर्थ उस क्षेत्र का अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जाएगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो।

**(ख) पौधा रोपण---**

(एक) काफी, चाय,रबर, आदि---

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम,निंबवंश,सेब आदि-----

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जाएगी और ऊपर उपश्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड [illegible]

**स्पष्टीकरण--** इस उप श्रेणी के प्रयोजन के [illegible] है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक, [illegible] प्रयोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनो के लिए किया जा सकता है।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

**छः-- आय या सम्पत्ति मानदण्ड**

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री--

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय एक लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 मे यथा / विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ के अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

**स्पष्टीकरण--** इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि

(एक) वेतन या कृषि भूमि से आय को मिलाया नहीं जाएगा।

(दो) रूपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो इसका अन्तराल कम भी हो सकता है।

आज्ञा से

**कालिका प्रसाद**

सचिव

Archana

Registrar
King George Medical University
Lucknow

# Chapter 6: Counselling and Reservation for Admission to MBBS and BDS Course

## 6.1 Admission Procedure

**6.1.1 Admissions to all seats of Undergraduate Medical / Dental Courses will be done through NEET (UG) - 2023. The following are the seats available under different quotas:**

- All India Quota Seats
- State Government Quota Seats
- Central Institutions/Universities/Deemed Universities
- State/Management/NRI Quota Seats in Private Medical / Dental Colleges or any Private University
- Central Pool Quota Seats
- All seats including NRI Quota as well as Management Quota, are in private unaided/aided minority / non-minority medical colleges.
- AIIMS Institutes across India/JIPMER.
- The Counselling for successful candidates for Seats under 15% All India Quota and 100% including 85% State quota seats of Central Institutions (ABVIMS & RML Hospital/VMMC & Safdarjung Hospital/ESIC)/ Central Universities (including DU/ BHU /AMU)/ AIIMS/ JIPMER and Deemed Universities, will be conducted by the MCC/DGHS for **Undergraduate Medical / Dental Courses**. MCC only does the registration for AFMC and forwards the data of registered Candidates to AFMC Authorities for the admission process**. DU/BHU and other Universities may use the score for any other relevant courses being offered by them.**

6.1.2 The counselling for admission to the seats under the control of State Governments/ UT Administrations / State Universities/ Institutions shall be conducted by the designated authorities of the State Governments as per the notifications issued separately by the authorities concerned.

6.1.3 The Result of NEET (UG) - 2023 **may** be utilized by other Entities of Central and State Governments, in accordance with their respective eligibility criteria / other norms /applicable regulations/guidelines/rules. The result data **may** also be utilized for B.Sc. (H) Nursing courses in accordance with their respective eligibility criteria / other norms /applicable regulations/guidelines/ rules. The NEET (UG) - 2023 data will also be used for admissions to **BVSc & AH courses** under the **15% quota of VCI i**n recognized Veterinary Colleges. However, the Council has to approach the MCC of DGHS, MoHFW in order to obtain the said data of results.

**Note: MNS (Military Nursing Services) aspirants seeking admission to BSc Nursing Course being conducted at Armed Forces Medical Service Hospitals for the year 2023 are required to qualify NEET and the NEET score will be used for shortlisting for selection to the four year BSc Nursing course.**

6.1.4 During counselling, the eligibility criteria, self-declaration, various documents, etc. of the eligible candidates shall be verified as per norms specified by the respective authorities and/or Medical / Dental Colleges. NTA does not have any responsibility towards the

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

correctness/genuinity of the uploaded information/documents during the application process.

6.1.5 **AACCC (Ayush Admissions Central Counselling Committee),** M/o Ayush shall be the counselling authority for **AIQ with respect to BAMS, BUMS and BSMS** courses under **NCISM and BHMS under NCH.**

6.1.6 An All India Merit List of the qualified candidates shall be prepared based on All India Rank in the Merit List of the NEET (UG) - 2023 and candidates shall be admitted to Undergraduate Medical Courses from the said list only, with existing reservation policy. NTA will only provide All India Rank to candidates while Admitting Authorities will invite applications for Counselling and a merit list shall be drawn based on All India Rank by the Admitting Authorities. Admission to Undergraduate Medical Courses within the respective categories shall be based solely on All India Rank as per merit list of NEET (UG) - 2023.

(a) **Admission in State Medical Colleges / Universities / Institutions / private medical colleges for seats other than 15% All India Quota:**

i. Admission under State Quota Seats shall be subject to reservation policy and eligibility criteria prevailing in the State/Union Territory as notified by the respective State/Union Territory from time to time.

ii. The reservation of the seats in medical colleges for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in the State/Union Territory concerned.

iii. Admission to **Undergraduate Medical Courses** in Private Medical Colleges shall be subject to policies of the Government of India/State/Union Territory.

(b) **Admission to AIIMS / JIPMER / Central Universities (DU/BHU/AMU) / AFMC / GGSIPU / ESIC Medical Colleges / Deemed Universities**

i. Counselling for admission to MBBS / BDS, etc. Courses in AIIMS / JIPMER / Central Universities [(including Medical Colleges under DU and Guru Govind Singh Indraprastha University (GGSIPU), BHU Medical College, AMU Medical College], ESIC Medical Colleges, and Deemed Universities will be conducted by DGHS, and reservation policy will be as per rules/regulations applicable to such Universities / Institutions. Candidates aspiring for admission to MBBS / BDS Courses in such Universities/ Institutions based upon their All India Rank (AIR) in NEET (UG) - 2023, shall have to register on the MCC website after the declaration of NEET (UG) - 2023 Result. The Candidate will have to register on the MCC Website. (**www.mcc.nic.in**). The list of registered candidates will be forwarded to AFMC authorities for conducting counselling at their end.

ii. Admission to AFMC, Pune shall be subject to the norms prescribed by the Directorate General of Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, Government of India. Candidates who apply for **NEET (UG) - 2023** and/or for seeking admission in **AFMC** also need to apply to AFMC on **https://afmc.nic.in/** The shortlisted candidates will be required to appear for



Registrar
King George Medical University
Lucknow

a second-stage Screening Test conducted by **AFMC**. Candidates are advised to contact **AFMC** for further and exact details. The Counselling will be conducted by **DGHS**.

iii. Admission to Medical Colleges under Central Universities (DU / BHU /AMU) /ESIC Medical Colleges /AFMC, shall be as per the provisions of the Statutory Regulations of NMC/ DCI, Deemed Universities relevant judgments of the Hon'ble Supreme Court of India, and the procedure prescribed by the Medical Counselling Committee (MCC) under the Directorate General of Health Services (DGHS).

iv. Further, the common counselling for admission to MBBS /BDS Courses in the concerned INIs shall be conducted by the DGHS as per the time schedule specified in the relevant Graduate Medical Education Regulation (1997) as amended from time to time.

(c) For all institutions, wherein Counselling is conducted by MCC under the DGHS, the candidates may refer to the Counselling scheme uploaded on the MCC website, so as to determine their eligibility to appear in Counselling for subsequent rounds, including in respect of ineligibility on account of allotment of seats in the previous rounds of Counselling in terms of Regulation 5A(4) of the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 which provides for preventing seat blocking in common Counselling for admission to MBBS course.

(d) For all institutions, wherein Counselling is conducted by the State/Union Govt. or its designated authority, the candidates may refer to the Counselling Notifications issued by the State/Union Govt. or its designated authority, so as to determine their eligibility to appear in Counselling for subsequent rounds, including in respect of ineligibility on account of allotment of seats in the previous rounds of Counselling in terms of Regulation 5A(4) of the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 which provides for preventing seat blocking in common Counselling for admission to MBBS.

## 6.2 Reservation Policy for Admission to MBBS and BDS Course

Indian nationals belonging to certain categories are admitted under the seats reserved for them in accordance with the rules prescribed by the Government of India. The categories and the extent of reservation are as follows:

- General category belonging to **Economically Weaker Section (GEN- EWS) – 10%** of seats in every course. The benefit of reservation will be given only to those General category candidates who satisfy the conditions given in the **OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17 January 2019,** issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The criteria for **GEN-EWS** will be as per the prevailing norms and/or notifications of the Government of India.
- Other Backward Classes belonging to the **Non-Creamy Layer (OBC- NCL) – 27%** of seats in every course.
    i. OBC-NCL should be listed in the current updated central list of OBC-NCL (**http://www.ncbc.nic.in**).
    ii. OBC-NCL present in the State list but **not** covered in the central list of OBC

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

NCL (as per the list in **http://www.ncbc.nic.in**) are **NOT** eligible to claim the reservation.

iii. The criteria for OBC-NCL will be as per the notification of the Government of India.

iv. Candidates belonging to the creamy layer of OBC are **NOT** entitled to reservation. Such candidates are treated as belonging to the general (GEN), i.e. unreserved category, and they will be eligible only for the GEN seats – the seats for which all candidates are eligible.

- **Scheduled Caste (SC) – 15%** of seats in every course.
- **Scheduled Tribe (ST) – 7.5%** of seats in every course.
- **Persons with Disability (PwBD)** – **5%** seats in each of GEN, GEN-EWS, OBC-NCL, SC, and ST category seats (Horizontal reservation).
    1. Candidates who want to avail the benefits of PwBD reservation in admission to MBBS/BDS course, the disability norms as prescribed by NMC (earlier known as MCI)/DCI norms will be adhered with, and only those candidates will be eligible for the benefit of reservation.

### 6.2.1 For Candidates claiming the GEN-EWS category

GEN-EWS certificate (**Appendix–VIIIA**) needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023 which should have been issued on or after 01 April 2022 in consonance with the latest guidelines of the Government of India. If any GEN-EWS candidate fails to submit the GEN-EWS certificate (issued on or after 01 April 2022) at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration [Declaration in Lieu of GEN-EWS Certificate at (**Appendix–VIIIB**)] to that effect (Reference: No.F.No.20013/01/2018-BC-II).

### 6.2.2 For Candidates claiming the OBC-NCL category

OBC-NCL certificate (**Appendix-IXA**) needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023 which should have been issued on or after 01 April 2022, in consonance with the latest guidelines of the Government of India. If any OBC-NCL candidate fails to upload the OBC- NCL certificate (issued on or after 01 April 2022) at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration [Declaration in Lieu of OBC-NCL Certificate as per **Appendix-IXB**] to that effect. Visit **http://www.ncbc.nic.in** for the latest guidelines and updates on the Central List of State-wise OBCs.

### 6.2.3 For Candidates claiming the SC or ST category

Caste (for SC) or tribe (for ST) certificate (**Appendix–XA**) needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023, in consonance with the latest guidelines of the Government of India. If any SC/ST candidate fails to upload the SC/ST certificate at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration [Declaration in Lieu of SC/ST Certificate as per **Appendix–XB**] to that effect.

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

### 6.3 Provisions relating to Persons with Disability (PwBD)

**Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities above 40% vide letter dated 29 August 2018 from Ministry of Social Justice and Empowerment.**

*As per Section 2(t) of the RPwD Act, **"Persons with Disability (PwD)"** means a person with long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.*

According to Section 2(r) of the RPwD Act, 2016, ***"persons with benchmark disabilities"*** means **a person with not less than forty percent (40%) of a specified disability** where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

The candidates with a Disability shall be considered for admission in medical course against 5% of the total seats, in accordance with the criteria prescribed under the Regulation on Graduate Medical Education (1997) as amended up to 13-05-2019 *(Please see* **Appendix-VI).**

### 6.4 Facilities for PwBD candidates to appear in the exam

As per the guidelines issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) under the Ministry of Social Justice and Empowerment issued from time to time on the subject: "Written Examination for Persons with Benchmark Disabilities", for the candidate with one of the benchmark disabilities [as defined in Section 2(r) of RPwD Act, 2016], holding a Disability Certificate in the prescribed format **(Appendix–XI)** in the Rights of Person with Disabilities Rules, 2017 (*link: https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_54_00002_201649_1517807328299&type=rule&filename=Rules_notified_15.06.pdf*).

*a)* *The facility of Scribe*, in case he/she has a **physical limitation and a scribe is essential to write the examination on his/her behalf**, being so certified in the aforesaid format by a CMO/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.

*b)* ***Compensatory time of one hour five minutes for examination of three hours twenty minutes (03:20 hrs)*** *duration for PwBD Candidate [having a physical limitation to write] will be given, whether such candidate uses the facility of Scribe or not.*

### 6.5 Services of a Scribe

As per the office memorandum of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Reference: **F. No. 34-02/2015-DD-III dated August 29, 2018**), the PwBD candidates who are visually impaired OR have a disability in the upper limbs OR have lost fingers/hands thereby preventing them from properly operating the Computer Based Test platform may avail the services of a Scribe (amanuensis).

The Scribe will help the Candidate in reading the questions and/or keying in the answers as per the directions of the Candidate. A Scribe will NEITHER explain the questions NOR suggest any solutions.

Archana

Registrar
King George Medical University
Lucknow

PwBD candidates who desire to avail the services of a Scribe need to opt for this during the online registration of NEET (UG) – 2023. If a candidate desires to bring his/her own Scribe, then he/she should submit a Letter of undertaking for using own Scribe as per the format available at **Appendix-XII**.

**It is to be noted that the Scribe may be provided by the National Testing Agency (NTA), if requested in the online Application Form of NEET (UG) - 2023.**

*If it is found at any stage that a candidate has availed the services of a Scribe and/or availed the compensatory time, but does not possess the extent of disability that warrants the use of a Scribe and/or grant of compensatory time, the candidate will be excluded from the process of evaluation, ranking, counselling, and admission. In case such a candidate has already been admitted to any Institution, the admission of the candidate will be cancelled.*

*The NTA does not guarantee any change in the category or sub-category (PwBD status) after the submission of the Online Application Form, and in any case, no change will be entertained by NTA after the declaration of NTA Score for NEET (UG) - 2023. Therefore, the candidates are advised to fill in the category/sub-category column very carefully.*

***Note:***

1. The minimum degree of disability should be **as per specified norms** in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the **Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)"** notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] on 4 January 2018.
3. No change in the category will be entertained after the last date specified by NTA for NEET (UG) - 2023 Registration.

- ***Candidates must note that the benefit of reservation will be given to them subject to verification of documents. If it is discovered at any stage that a candidate has used a false/fake/incorrect document, or has furnished false, incorrect, or incomplete information, in order to avail the benefit of reservation, then such a candidate shall be excluded from all admission processes. In case such a candidate has already been given admission, the admission shall stand cancelled.***

Physical Disability certificate (Unique Disability Identification (UDID) issued by the notified medical authority needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023.

In the case of the Institutes run/aided/recognized by State Governments, the reservation policy of the respective State Governments shall be applicable.

Guidelines for conducting written examination for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwBD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing:

***Notes:***

1. *The benefit of reservation for admission shall be given only to those classes/castes/tribes which are in the respective Central List published by the Government of India from time to time.*
2. *The benefit of reservation will be given only to those castes and tribes that are mentioned in the respective central list of corresponding states published by the Government of India (websites: http://socialjustice.nic.in and https://ncst.nic.in).*

Registrar
King George Medical University
Lucknow

I. These guidelines may be called as Guidelines for conducting written examination for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwBD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

II. The facility of Scribe and/or compensatory time shall be granted solely to those having difficulty in writing subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that Scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-XII.

III. The medical authority for the purpose of certification as mentioned in point (II) above should be a multi-member authority comprising the following:-

- *i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....Chairperson*
- *ii. Orthopaedic/PMR specialist*
- *iii. Neurologist, if available**
- *iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/Special Educator*
- *v. Occupational therapist, if available**
- *vi. Any other expert based on the condition of the candidate as may be nominated by the Chairperson. (* the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer may make full efforts for inclusion of neurologists, occupational therapist from the nearest District or the Medical College/Institute, if the same is not available in the District)"*

IV. Compensatory time not less than 20 minutes per hour of the examination should be allowed for persons who are eligible for getting Scribe. In case the duration of the examination is less than an hour, then the duration of the compensatory time should be allowed on prorata basis. Compensatory time should not be less than 5 minutes and should be in the multiple of 5.

## 6.6 Reservation in Central Institutes / Universities

The reservation policy of the Government of India is applicable to NEET (UG) Examination. According to this, in the Central Universities and Institutions, 10% of the seats are reserved for the category General-Economically Weaker Section (GEN-EWS), 15% of the seats are reserved for the category Scheduled Caste (SC), 7.5% for the category Scheduled Tribe (ST), 27% for the category Other Backward Classes belonging to the Non-Creamy Layer (OBC-NCL) and 5% seats **(Horizontal Reservation) for PwBD candidates**.

Reservation in State Quota Seats/Universities/Institutions /Private Medical Colleges under State Governments: In case of seats filled by the State Medical Colleges/Universities/Institutions /Private Medical Colleges under State Quota Seats, the reservation policy of the concerned State Government shall apply.

## 6.7 Guidelines for PwBD Candidates

**a.** The candidates with a Disability shall be considered for admission in medical course against 5% of the total seats, in accordance with the criteria prescribed under the Regulation on Graduate Medical Education (1997) as amended up to 13-05-2019 *(Please see **Appendix-VI**).*

b. Candidates who consider themselves eligible for this category are advised to ensure their eligibility by getting themselves examined at any Government Medical College/District Hospital/Government Hospital. Such Government Medical College/District Hospital/Government Hospital shall issue a Disability Certificate in reference to Chapter-VII of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. Such a Disability Certificate is issued as per the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and the Guidelines for the purpose of assessing the extent of

Registrar
King George Medical University
Lucknow

specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] on 4th January 2018 and does not confer any right on any candidate to seek admission in a medical course under PwBD Quota. The aforesaid Certificate shall be to ascertain whether a candidate can apply to NTA for appearing in NEET (UG) - 2023 under the PwBD Quota only.

c. Thereafter, the candidates, upon selection under PwBD Category, shall have to produce a Disability Certificate issued by the Disability Assessment Board, which shall have assessed the candidate in reference to criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 as amended up to 13.05.2019. Thus, it is relevant that the candidates after a declaration of the result have to appear before the 16 designated Disability Assessment Board so as to determine whether they may register or participate in the common online Counselling towards admission to medical courses.

**List of the 16 Designated Disability centres has been annexed (Appendix-VII).**

d. In case candidates are found to be ineligible by the 16 designated Disability Assessment Board, in reference to criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 as amended on 14.05.2019, they **may not** register or participate in the common online Counselling and any online provisional allotment of the medical college shall be entirely fraudulent on the part of the candidate. It is relevant that physical verification of various certificates including academic as well as Disability Certificate is only upon reporting for admission to the medical college.

e. It is further clarified that the certificates issued by the authorized Centres designated for the purpose by DGHS, shall only be considered for admission to the medical courses and no other certificate issued by any other Government Medical College/District Hospital/Government Hospital will be accepted.

f. **The Disability Certificate to be issued in the format given in Appendix-XI has to be issued by the designated Centres,** as per the criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education (1997) as amended upto 14.05.2019, w.r.t. common counselling conducted by MCC / DGHS for All India Quota seats and for Medical Institutions that are subject to common counselling of MCC/ DGHS.

g. Likewise, the designated Counselling Authorities of State/UT Governments shall constitute Disability Assessment Boards/Centres for assessing the suitability of the candidate in reference to criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education (1997) as amended up to 14.05.2019 and shall notify the same on their respective websites.

h. The reservation policy, as prescribed by the government from time to time will be followed by the admitting institutes. The candidates are advised to look for the details at the time of admission.

## 6.8 Instructions for Counselling by the MCC for MBBS and BDS Admission

i. Online counselling would be conducted by the Medical Counselling Committee (MCC) of the Directorate General of Health Services for Undergraduate Medical Courses. Information for online counselling would only be available on the MCC website

Registrar
King George Medical University
Lucknow

(https://mcc.nic.in/UGCounselling/) for Undergraduate Medical/Dental Courses. Qualified candidates are advised to read the counselling-related information carefully and understand the course of action to be taken by them for appearing in the Counselling.

ii. MCC is conducting Counselling for:

A. 15% All India Quota seats MBBS/BDS seats of States (Including J&K)
B. 100% MBBS/ BDS Seats of BHU OPEN
C. AIIMS Open seats- 100% MBBS Seats of AIIMS across India
D. JIPMER Open (Puducherry/ Karaikal) & Internal seats (Domicile)
E. AMU Open & Internal seats
F. 85% Internal quota/domicile seats of DU/I.P University (VMMC/BVIMS/ESIC Dental)
G. Jamia Open seats- Faculty of Dentistry (Jamia Milia Islamia) & Internal seats
H. 15% All India Quota Seats of ESIC & Insured Persons quota seats
I. AFMC – Only registration
J. 100% B. Sc (Nursing) of selected Central B.Sc. Nursing Institutes in accordance with their respective eligibility criteria /other norms/ applicable regulations/ guidelines/ rules.

**iii.** Any query related to Counselling for admission to seats under 15% All India Quota and in Central Institutions / Universities, including AIIMS/JIPMER/AFMC/ESIC/DU/BHU/ AMU, and Deemed Universities, may be referred to the following address: For MBBS/BDS Courses: **Office of MCC, Directorate General of Health Services (DGHS), Nirman Bhawan, New Delhi- 110108, E-mail: aipmt-mcc@nic.in, Toll Free Nos: 1800-102-7637, 0120-4073500.**

iv. **Reservation policy for 15% AIQ, Central Institutes (ABVIMS & RML and VMMC & SJH, ESIC) Universities (DU, AMU, BHU)/AIIMS/JIPMER is as follows**:

Reservation Policy of the Central Government for the NEET (UG) Counselling in All India Quota/Central Institutes (ABVIMS & RML and VMMC & SJH, ESIC) Universities (DU, AMU, BHU)/AIIMS/JIPMER is as follows:

- S.C- 15 %
- S.T- 7.5 %
- PwBD- 5 % Horizontal Reservation
- OBC (Non-Creamy Layer)- 27% as per Central List of OBC
- EWS- 10 % as per Central Government Norms

**Reservation Policy for Deemed University is as follows:**

- **NRI Quota**
- **Jain & Muslim Minority**

v. Candidates from the creamy layer and those who do not come under the Central List of OBC are advised to mention their category as Unreserved/General.

vi. The disability centres in the MCC chapter that "for participating in the MCC counselling, the disability certificate uploaded in MCC Information Bulletin may be referred which must be issued by one of the 16 Designated Disability issuing Certificate Boards".

**For MBBS/BDS Courses:**

**The Deputy Director General (ME)**
**Directorate General of Health Services,**
**Nirman Bhawan, New Delhi-110 108**
**E-mail: adgme@nic.in**
**https://mcc.nic.in/UGCounselling/Home/ContactUs**

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

# Chapter 6: Counselling and Reservation for Admission to MBBS and BDS Course

## 6.1 Admission Procedure

**6.1.1 Admissions to all seats of Undergraduate Medical / Dental Courses will be done through NEET (UG) - 2023. The following are the seats available under different quotas:**

- All India Quota Seats
- State Government Quota Seats
- Central Institutions/Universities/Deemed Universities
- State/Management/NRI Quota Seats in Private Medical / Dental Colleges or any Private University
- Central Pool Quota Seats
- All seats including NRI Quota as well as Management Quota, are in private unaided/aided minority / non-minority medical colleges.
- AIIMS Institutes across India/JIPMER.
- The Counselling for successful candidates for Seats under 15% All India Quota and 100% including 85% State quota seats of Central Institutions (ABVIMS & RML Hospital/VMMC & Safdarjung Hospital/ESIC)/ Central Universities (including DU/ BHU /AMU)/ AIIMS/ JIPMER and Deemed Universities, will be conducted by the MCC/DGHS for **Undergraduate Medical / Dental Courses**. MCC only does the registration for AFMC and forwards the data of registered Candidates to AFMC Authorities for the admission process. **DU/BHU and other Universities may use the score for any other relevant courses being offered by them.**

6.1.2 The counselling for admission to the seats under the control of State Governments/ UT Administrations / State Universities/ Institutions shall be conducted by the designated authorities of the State Governments as per the notifications issued separately by the authorities concerned.

6.1.3 The Result of NEET (UG) - 2023 **may** be utilized by other Entities of Central and State Governments, in accordance with their respective eligibility criteria / other norms /applicable regulations/guidelines/rules. The result data **may** also be utilized for B.Sc. (H) Nursing courses in accordance with their respective eligibility criteria / other norms /applicable regulations/guidelines/ rules. The NEET (UG) - 2023 data will also be used for admissions to **BVSc & AH courses** under the **15% quota of VCI i**n recognized Veterinary Colleges. However, the Council has to approach the MCC of DGHS, MoHFW in order to obtain the said data of results.

**Note: MNS (Military Nursing Services) aspirants seeking admission to BSc Nursing Course being conducted at Armed Forces Medical Service Hospitals for the year 2023 are required to qualify NEET and the NEET score will be used for shortlisting for selection to the four year BSc Nursing course.**

6.1.4 During counselling, the eligibility criteria, self-declaration, various documents, etc. of the eligible candidates shall be verified as per norms specified by the respective authorities and/or Medical / Dental Colleges. NTA does not have any responsibility towards the



Registrar
King George Medical University
Lucknow

correctness/genuinity of the uploaded information/documents during the application process.

6.1.5 **AACCC (Ayush Admissions Central Counselling Committee),** M/o Ayush shall be the counselling authority for **AIQ with respect to BAMS, BUMS and BSMS** courses under **NCISM and BHMS under NCH.**

6.1.6 An All India Merit List of the qualified candidates shall be prepared based on All India Rank in the Merit List of the NEET (UG) - 2023 and candidates shall be admitted to Undergraduate Medical Courses from the said list only, with existing reservation policy. NTA will only provide All India Rank to candidates while Admitting Authorities will invite applications for Counselling and a merit list shall be drawn based on All India Rank by the Admitting Authorities. Admission to Undergraduate Medical Courses within the respective categories shall be based solely on All India Rank as per merit list of NEET (UG) - 2023.

(a) **Admission in State Medical Colleges / Universities / Institutions / private medical colleges for seats other than 15% All India Quota:**

i. Admission under State Quota Seats shall be subject to reservation policy and eligibility criteria prevailing in the State/Union Territory as notified by the respective State/Union Territory from time to time.

ii. The reservation of the seats in medical colleges for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in the State/Union Territory concerned.

iii. Admission to **Undergraduate Medical Courses** in Private Medical Colleges shall be subject to policies of the Government of India/State/Union Territory.

(b) **Admission to AIIMS / JIPMER / Central Universities (DU/BHU/AMU) / AFMC / GGSIPU / ESIC Medical Colleges / Deemed Universities**

i. Counselling for admission to MBBS / BDS, etc. Courses in AIIMS / JIPMER / Central Universities [(including Medical Colleges under DU and Guru Govind Singh Indraprastha University (GGSIPU), BHU Medical College, AMU Medical College], ESIC Medical Colleges, and Deemed Universities will be conducted by DGHS, and reservation policy will be as per rules/regulations applicable to such Universities / Institutions. Candidates aspiring for admission to MBBS / BDS Courses in such Universities/ Institutions based upon their All India Rank (AIR) in NEET (UG) - 2023, shall have to register on the MCC website after the declaration of NEET (UG) - 2023 Result. The Candidate will have to register on the MCC Website. (**www.mcc.nic.in**). The list of registered candidates will be forwarded to AFMC authorities for conducting counselling at their end.

ii. Admission to AFMC, Pune shall be subject to the norms prescribed by the Directorate General of Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, Government of India. Candidates who apply for **NEET (UG) - 2023** and/or for seeking admission in **AFMC** also need to apply to AFMC on **https://afmc.nic.in/** The shortlisted candidates will be required to appear for

Registrar
King George Medical University
Lucknow

a second-stage Screening Test conducted by **AFMC**. Candidates are advised to contact **AFMC** for further and exact details. The Counselling will be conducted by **DGHS**.

iii. Admission to Medical Colleges under Central Universities (DU / BHU /AMU) /ESIC Medical Colleges /AFMC, shall be as per the provisions of the Statutory Regulations of NMC/ DCI, Deemed Universities relevant judgments of the Hon'ble Supreme Court of India, and the procedure prescribed by the Medical Counselling Committee (MCC) under the Directorate General of Health Services (DGHS).

iv. Further, the common counselling for admission to MBBS /BDS Courses in the concerned INIs shall be conducted by the DGHS as per the time schedule specified in the relevant Graduate Medical Education Regulation (1997) as amended from time to time.

(c) For all institutions, wherein Counselling is conducted by MCC under the DGHS, the candidates may refer to the Counselling scheme uploaded on the MCC website, so as to determine their eligibility to appear in Counselling for subsequent rounds, including in respect of ineligibility on account of allotment of seats in the previous rounds of Counselling in terms of Regulation 5A(4) of the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 which provides for preventing seat blocking in common Counselling for admission to MBBS course.

(d) For all institutions, wherein Counselling is conducted by the State/Union Govt. or its designated authority, the candidates may refer to the Counselling Notifications issued by the State/Union Govt. or its designated authority, so as to determine their eligibility to appear in Counselling for subsequent rounds, including in respect of ineligibility on account of allotment of seats in the previous rounds of Counselling in terms of Regulation 5A(4) of the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 which provides for preventing seat blocking in common Counselling for admission to MBBS.

## 6.2 Reservation Policy for Admission to MBBS and BDS Course

Indian nationals belonging to certain categories are admitted under the seats reserved for them in accordance with the rules prescribed by the Government of India. The categories and the extent of reservation are as follows:

- General category belonging to **Economically Weaker Section (GEN- EWS) – 10%** of seats in every course. The benefit of reservation will be given only to those General category candidates who satisfy the conditions given in the **OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17 January 2019,** issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The criteria for **GEN-EWS** will be as per the prevailing norms and/or notifications of the Government of India.
- Other Backward Classes belonging to the **Non-Creamy Layer (OBC- NCL) – 27%** of seats in every course.
  - i. OBC-NCL should be listed in the current updated central list of OBC-NCL (**http://www.ncbc.nic.in**).
  - ii. OBC-NCL present in the State list but **not** covered in the central list of OBC

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

NCL (as per the list in **http://www.ncbc.nic.in**) are **NOT** eligible to claim the reservation.

iii. The criteria for OBC-NCL will be as per the notification of the Government of India.

iv. Candidates belonging to the creamy layer of OBC are **NOT** entitled to reservation. Such candidates are treated as belonging to the general (GEN), i.e. unreserved category, and they will be eligible only for the GEN seats – the seats for which all candidates are eligible.

- **Scheduled Caste (SC) – 15%** of seats in every course.
- **Scheduled Tribe (ST) – 7.5%** of seats in every course.
- **Persons with Disability (PwBD)** – **5%** seats in each of GEN, GEN-EWS, OBC-NCL, SC, and ST category seats (Horizontal reservation).
    1. Candidates who want to avail the benefits of PwBD reservation in admission to MBBS/BDS course, the disability norms as prescribed by NMC (earlier known as MCI)/DCI norms will be adhered with, and only those candidates will be eligible for the benefit of reservation.

### 6.2.1 For Candidates claiming the GEN-EWS category

GEN-EWS certificate (**Appendix–VIIIA**) needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023 which should have been issued on or after 01 April 2022 in consonance with the latest guidelines of the Government of India. If any GEN-EWS candidate fails to submit the GEN-EWS certificate (issued on or after 01 April 2022) at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration [Declaration in Lieu of GEN-EWS Certificate at (**Appendix–VIIIB**)] to that effect (Reference: No.F.No.20013/01/2018-BC-II).

### 6.2.2 For Candidates claiming the OBC-NCL category

OBC-NCL certificate (**Appendix-IXA**) needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023 which should have been issued on or after 01 April 2022, in consonance with the latest guidelines of the Government of India. If any OBC-NCL candidate fails to upload the OBC- NCL certificate (issued on or after 01 April 2022) at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration [Declaration in Lieu of OBC-NCL Certificate as per **Appendix-IXB**] to that effect. Visit **http://www.ncbc.nic.in** for the latest guidelines and updates on the Central List of State-wise OBCs.

### 6.2.3 For Candidates claiming the SC or ST category

Caste (for SC) or tribe (for ST) certificate (**Appendix–XA**) needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023, in consonance with the latest guidelines of the Government of India. If any SC/ST candidate fails to upload the SC/ST certificate at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration [Declaration in Lieu of SC/ST Certificate as per **Appendix–XB**] to that effect.

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

## 6.3 Provisions relating to Persons with Disability (PwBD)

**Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities above 40% vide letter dated 29 August 2018 from Ministry of Social Justice and Empowerment.**

*As per Section 2(t) of the RPwD Act, **"Persons with Disability (PwD)"** means a person with long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.*

According to Section 2(r) of the RPwD Act, 2016, ***"persons with benchmark disabilities"*** means **a person with not less than forty percent (40%) of a specified disability** where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

The candidates with a Disability shall be considered for admission in medical course against 5% of the total seats, in accordance with the criteria prescribed under the Regulation on Graduate Medical Education (1997) as amended up to 13-05-2019 *(Please see* **Appendix-VI).**

## 6.4 Facilities for PwBD candidates to appear in the exam

As per the guidelines issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) under the Ministry of Social Justice and Empowerment issued from time to time on the subject: "Written Examination for Persons with Benchmark Disabilities", for the candidate with one of the benchmark disabilities [as defined in Section 2(r) of RPwD Act, 2016], holding a Disability Certificate in the prescribed format **(Appendix–XI)** in the Rights of Person with Disabilities Rules, 2017 (*link: https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_54_00002_201649_1517807328299&type=rule&filename=Rules_notified_15.06.pdf*).

a) *The facility of Scribe*, in case he/she has a **physical limitation and a scribe is essential to write the examination on his/her behalf**, being so certified in the aforesaid format by a CMO/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.
b) ***Compensatory time of one hour five minutes for examination of three hours twenty minutes (03:20 hrs)*** *duration for PwBD Candidate [having a physical limitation to write] will be given, whether such candidate uses the facility of Scribe or not.*

## 6.5 Services of a Scribe

As per the office memorandum of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Reference: **F. No. 34-02/2015-DD-III dated August 29, 2018**), the PwBD candidates who are visually impaired OR have a disability in the upper limbs OR have lost fingers/hands thereby preventing them from properly operating the Computer Based Test platform may avail the services of a Scribe (amanuensis).

The Scribe will help the Candidate in reading the questions and/or keying in the answers as per the directions of the Candidate. A Scribe will NEITHER explain the questions NOR suggest any solutions.

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

PwBD candidates who desire to avail the services of a Scribe need to opt for this during the online registration of NEET (UG) – 2023. If a candidate desires to bring his/her own Scribe, then he/she should submit a Letter of undertaking for using own Scribe as per the format available at **Appendix-XII**.

**It is to be noted that the Scribe may be provided by the National Testing Agency (NTA), if requested in the online Application Form of NEET (UG) - 2023.**

*If it is found at any stage that a candidate has availed the services of a Scribe and/or availed the compensatory time, but does not possess the extent of disability that warrants the use of a Scribe and/or grant of compensatory time, the candidate will be excluded from the process of evaluation, ranking, counselling, and admission. In case such a candidate has already been admitted to any Institution, the admission of the candidate will be cancelled.*

*The NTA does not guarantee any change in the category or sub-category (PwBD status) after the submission of the Online Application Form, and in any case, no change will be entertained by NTA after the declaration of NTA Score for NEET (UG) - 2023. Therefore, the candidates are advised to fill in the category/sub-category column very carefully.*

***Note:***

1. The minimum degree of disability should be **as per specified norms** in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the **Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)"** notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] on 4 January 2018.
3. No change in the category will be entertained after the last date specified by NTA for NEET (UG) - 2023 Registration.

- ***Candidates must note that the benefit of reservation will be given to them subject to verification of documents. If it is discovered at any stage that a candidate has used a false/fake/incorrect document, or has furnished false, incorrect, or incomplete information, in order to avail the benefit of reservation, then such a candidate shall be excluded from all admission processes. In case such a candidate has already been given admission, the admission shall stand cancelled.***

Physical Disability certificate (Unique Disability Identification (UDID) issued by the notified medical authority needs to be uploaded in the Online Application Form of NEET (UG) – 2023.

In the case of the Institutes run/aided/recognized by State Governments, the reservation policy of the respective State Governments shall be applicable.

Guidelines for conducting written examination for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwBD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing:

***Notes:***

1. *The benefit of reservation for admission shall be given only to those classes/castes/tribes which are in the respective Central List published by the Government of India from time to time.*
2. *The benefit of reservation will be given only to those castes and tribes that are mentioned in the respective central list of corresponding states published by the Government of India (websites: http://socialjustice.nic.in and https://ncst.nic.in).*

Registrar
King George Medical University
Lucknow

I. These guidelines may be called as Guidelines for conducting written examination for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwBD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

II. The facility of Scribe and/or compensatory time shall be granted solely to those having difficulty in writing subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that Scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-XII.

III. The medical authority for the purpose of certification as mentioned in point (II) above should be a multi-member authority comprising the following:-

   i. *Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....Chairperson*
   ii. *Orthopaedic/PMR specialist*
   iii. *Neurologist, if available**
   iv. *Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/Special Educator*
   v. *Occupational therapist, if available**
   vi. *Any other expert based on the condition of the candidate as may be nominated by the Chairperson. (* the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer may make full efforts for inclusion of neurologists, occupational therapist from the nearest District or the Medical College/Institute, if the same is not available in the District)"*

IV. Compensatory time not less than 20 minutes per hour of the examination should be allowed for persons who are eligible for getting Scribe. In case the duration of the examination is less than an hour, then the duration of the compensatory time should be allowed on prorata basis. Compensatory time should not be less than 5 minutes and should be in the multiple of 5.

## 6.6 Reservation in Central Institutes / Universities

The reservation policy of the Government of India is applicable to NEET (UG) Examination. According to this, in the Central Universities and Institutions, 10% of the seats are reserved for the category General-Economically Weaker Section (GEN-EWS), 15% of the seats are reserved for the category Scheduled Caste (SC), 7.5% for the category Scheduled Tribe (ST), 27% for the category Other Backward Classes belonging to the Non-Creamy Layer (OBC-NCL) and 5% seats **(Horizontal Reservation) for PwBD candidates**.

Reservation in State Quota Seats/Universities/Institutions /Private Medical Colleges under State Governments: In case of seats filled by the State Medical Colleges/Universities/Institutions /Private Medical Colleges under State Quota Seats, the reservation policy of the concerned State Government shall apply.

## 6.7 Guidelines for PwBD Candidates

**a.** The candidates with a Disability shall be considered for admission in medical course against 5% of the total seats, in accordance with the criteria prescribed under the Regulation on Graduate Medical Education (1997) as amended up to 13-05-2019 *(Please see **Appendix-VI**).*

b. Candidates who consider themselves eligible for this category are advised to ensure their eligibility by getting themselves examined at any Government Medical College/District Hospital/Government Hospital. Such Government Medical College/District Hospital/Government Hospital shall issue a Disability Certificate in reference to Chapter-VII of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. Such a Disability Certificate is issued as per the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and the Guidelines for the purpose of assessing the extent of

Registrar
King George Medical University
Lucknow

specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] on 4th January 2018 and does not confer any right on any candidate to seek admission in a medical course under PwBD Quota. The aforesaid Certificate shall be to ascertain whether a candidate can apply to NTA for appearing in NEET (UG) - 2023 under the PwBD Quota only.

c. Thereafter, the candidates, upon selection under PwBD Category, shall have to produce a Disability Certificate issued by the Disability Assessment Board, which shall have assessed the candidate in reference to criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 as amended up to 13.05.2019. Thus, it is relevant that the candidates after a declaration of the result have to appear before the 16 designated Disability Assessment Board so as to determine whether they may register or participate in the common online Counselling towards admission to medical courses.

**List of the 16 Designated Disability centres has been annexed (Appendix-VII).**

d. In case candidates are found to be ineligible by the 16 designated Disability Assessment Board, in reference to criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 as amended on 14.05.2019, they **may not** register or participate in the common online Counselling and any online provisional allotment of the medical college shall be entirely fraudulent on the part of the candidate. It is relevant that physical verification of various certificates including academic as well as Disability Certificate is only upon reporting for admission to the medical college.

e. It is further clarified that the certificates issued by the authorized Centres designated for the purpose by DGHS, shall only be considered for admission to the medical courses and no other certificate issued by any other Government Medical College/District Hospital/Government Hospital will be accepted.

f. **The Disability Certificate to be issued in the format given in Appendix-XI has to be issued by the designated Centres,** as per the criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education (1997) as amended upto 14.05.2019, w.r.t. common counselling conducted by MCC / DGHS for All India Quota seats and for Medical Institutions that are subject to common counselling of MCC/ DGHS.

g. Likewise, the designated Counselling Authorities of State/UT Governments shall constitute Disability Assessment Boards/Centres for assessing the suitability of the candidate in reference to criteria prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education (1997) as amended up to 14.05.2019 and shall notify the same on their respective websites.

h. The reservation policy, as prescribed by the government from time to time will be followed by the admitting institutes. The candidates are advised to look for the details at the time of admission.

### 6.8 Instructions for Counselling by the MCC for MBBS and BDS Admission

i. Online counselling would be conducted by the Medical Counselling Committee (MCC) of the Directorate General of Health Services for Undergraduate Medical Courses. Information for online counselling would only be available on the MCC website



Registrar
King George Medical University
Lucknow

(https://mcc.nic.in/UGCounselling/) for Undergraduate Medical/Dental Courses. Qualified candidates are advised to read the counselling-related information carefully and understand the course of action to be taken by them for appearing in the Counselling.

ii. MCC is conducting Counselling for:

A. 15% All India Quota seats MBBS/BDS seats of States (Including J&K)
B. 100% MBBS/ BDS Seats of BHU OPEN
C. AIIMS Open seats- 100% MBBS Seats of AIIMS across India
D. JIPMER Open (Puducherry/ Karaikal) & Internal seats (Domicile)
E. AMU Open & Internal seats
F. 85% Internal quota/domicile seats of DU/I.P University (VMMC/BVIMS/ESIC Dental)
G. Jamia Open seats- Faculty of Dentistry (Jamia Milia Islamia) & Internal seats
H. 15% All India Quota Seats of ESIC & Insured Persons quota seats
I. AFMC – Only registration
J. 100% B. Sc (Nursing) of selected Central B.Sc. Nursing Institutes in accordance with their respective eligibility criteria /other norms/ applicable regulations/ guidelines/ rules.

**iii.** Any query related to Counselling for admission to seats under 15% All India Quota and in Central Institutions / Universities, including AIIMS/JIPMER/AFMC/ESIC/DU/BHU/ AMU, and Deemed Universities, may be referred to the following address: For MBBS/BDS Courses: **Office of MCC, Directorate General of Health Services (DGHS), Nirman Bhawan, New Delhi- 110108, E-mail: aipmt-mcc@nic.in, Toll Free Nos: 1800-102-7637, 0120-4073500.**

iv. **Reservation policy for 15% AIQ, Central Institutes (ABVIMS & RML and VMMC & SJH, ESIC) Universities (DU, AMU, BHU)/AIIMS/JIPMER is as follows**:

Reservation Policy of the Central Government for the NEET (UG) Counselling in All India Quota/Central Institutes (ABVIMS & RML and VMMC & SJH, ESIC) Universities (DU, AMU, BHU)/AIIMS/JIPMER is as follows:

- S.C- 15 %
- S.T- 7.5 %
- PwBD- 5 % Horizontal Reservation
- OBC (Non-Creamy Layer)- 27% as per Central List of OBC
- EWS- 10 % as per Central Government Norms

**Reservation Policy for Deemed University is as follows:**

- **NRI Quota**
- **Jain & Muslim Minority**

v. Candidates from the creamy layer and those who do not come under the Central List of OBC are advised to mention their category as Unreserved/General.

vi. The disability centres in the MCC chapter that "for participating in the MCC counselling, the disability certificate uploaded in MCC Information Bulletin may be referred which must be issued by one of the 16 Designated Disability issuing Certificate Boards".

**For MBBS/BDS Courses:**

**The Deputy Director General (ME)**
**Directorate General of Health Services,**
**Nirman Bhawan, New Delhi-110 108**
**E-mail: adgme@nic.in**
**https://mcc.nic.in/UGCounselling/Home/ContactUs**

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow